

195-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम०के०सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 2138-एक/2016 - विरुद्ध - आदेश
दिनांक 22-2-2014 - पारित द्वारा एडीशनल कमिश्नर,
जबलपुर संभाग, जबलपुर- प्रकरण क्रमांक 1288 अ-21/
2012-13 अपील

संगीता पुत्री प्रताप सिंह ठाकुर
निवासी सिविल लायन कटनी
तहसील व जिला कटनी म०प्र०
विरुद्ध

---अपीलांत

मध्य प्रदेश शासन

---उत्तरवादी

(आवेदक के अभिभाषक श्री एम०एस०नब्बी)

आ दे श

(आज दिनांक 19-1-2017 को पारित)

यह अपील एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा
प्रकरण क्रमांक 1288 अ-21/ 2012-13 अपील में पारित आदेश
दिनांक 22-2-2014 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959
की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोश यह है अपीलांत ने कलेक्टर कटनी को आवेदन
प्रस्तुत कर मांग की कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम भदौरा स्थित
भूमि खसरा नंबर 133 एवं 137 कुल किता 2 कुल रकबा 3.01 हैक्टर
(आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) असिंचित एवं पड़त
भूमि है, जिसे वह विक्रय करना चाहती है। विक्रय से प्राप्त धन से बाबू





जगजीवन राम वार्ड -16 स्थित जैन कालोनी के 1250 वर्गफुट प्लाट पर मकान बनायेगी एवं ग्राम सलैया की भूमि आधुनिक तरीके से खेती योग्य बनाने में खर्च करेगी, इसलिये भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे। कलेक्टर कटनी ने प्रकरण क्रमांक 36 अ-21/12-13 पंजीबद्ध किया तथा अपीलांट के आवेदन की जांच अनुविभागीय अधिकारी कटनी एवं तहसीलदार बड़वारा से कराई। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अपीलांट को सुनकर आदेश दिनांक 16-8-13 पारित करके अपीलांट का विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलांट ने एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 1288 अ-21/ 2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-2-2014 से निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

4/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से परिलक्षित है कि कलेक्टर कटनी ने अपीलांट के आवेदन की जांच अनुविभागीय अधिकारी कटनी एवं तहसीलदार बड़वारा से कराई है। कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 36 अ-21/12-13 में तहसीलदार बड़वारा का जांच प्रतिवेदन दिनांक 1-9-2012 संलग्न है जिसके पद 3 में इस प्रकार उल्लेखित है :-

“ आवेदिका के पास ग्राम भदौरा नं.1 तहसील बड़वारा में ख.नं. 133, 137 कुल रकबा 3.01 है. असिंचित पड़त भूमि एवं ग्राम सलैया तहसील कटनी में ख.नं. 240, 526, 673, 704, 706, 708, 710,745, 851/1, 862, 868 कुल रकबा 7.06 है. भूमि है। ”

प्रतिवेदन के अंत में अंकित किया है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदिका को भूमि विक्रय की अनुमति देना उचित प्रतीत होता है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट को शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है

Rja

M

अपितु विक्रय पत्र द्वारा अर्जित होकर शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है जिसे कलेक्टर कटनी ने आदेश दिनांक 16-8-13 में स्वीकार किया है। विचार योग्य है कि क्या अपीलांत उसके द्वारा कय की गई एवं अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज भूमि विक्रय कर सकती है ?

1. फुल्ला विरुद्ध नरेन्द्र सिंह तथा अन्य 2012 रा०नि० 256 (उच्च न्यायालय) का न्यायिक दृष्टांत है कि म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7-ख) तथा 158(3) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन से पूर्व पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये - बिना अनुमति भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया- उपबंध आकर्षित नहीं होते । भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।
2. (1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० विरुद्ध म०प्र० राज्य तथा अन्य एक 2013 रा०नि० 8(उच्च न्यायालय) का दृष्टांत है कि म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7-ख) तथा 158(3) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन के पूर्व का पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार दिये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया-उपबंध आकर्षित नहीं होते।
(2) विधि का सिद्धांत - नवीन उपबंध का अंतःस्थापन- भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया-ऐसे उपबंध की भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।

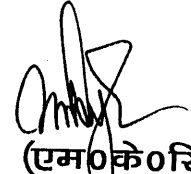
वादग्रस्त भूमि अपीलांत की कयशुदा भूमि होकर अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है जिसके कारण भूमि की विक्रय अनुमति दिये जाने में बैधानिक अड़चन नहीं है किन्तु कलेक्टर कटनी ने आदेश दिनांक 16-8-13 पारित करते समय तथा एडीशनल कमिश्नर, जबलपुरसंभाग, जबलपुर द्वारा आदेश दिनांक 22-2-2014 पारित करते समय उक्त की अनदेखी की है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।





5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1288 अ-21/ 2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-2-2014 तथा कलेक्टर कटनी द्वारा प्र0क0 36 अ-21/ 12-13 में पारित आदेश दिनांक 16-8-13 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एवं अपीलांत को ग्राम भदौरा स्थित भूमि खसरा नंबर 133 एवं 137 कुल किता 2 कुल रकबा 3.01 हैक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. भूमि का कय-विक्रय इस आदेश के तीन माह के भीतर संपन्न करा लिया जावेगा। तीन माह की अवधि व्यतीत होने के उपरांत यह आदेश निष्प्रभावी होगा।
2. उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित करते समय ध्यान रखेंगे कि भूमि का विक्रय वर्तमान में शासन की प्रचलित गाईड लायन के मान से एवं शासन द्वारा कय-विक्रय हेतु वर्तमान में जारी नियम/निर्देशों के पालन करते हुये हो रहा है अथवा नहीं।



(एम0के0सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर

